

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दुबई में दुनिया के उद्योग जगत को दिया न्योता

मप्र निवेशकों का भरोसेमंद साथी

25 से अधिक नई नीतियां

निवेश और कारोबार को आसान बनाने के लिए 25 से अधिक नयी नीतियां और 2700 से अधिक अप्रासरणिक कानून समाप्ता।

76 हजार करोड़ रुपए से अधिक निर्यात

वर्ष 2026-27 में मध्यप्रदेश से 76 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात। रीवा, इंदौर और उज्जैन में तीन नए आईटी पार्क विकसित किए जा रहे हैं।

भूमि-बिजली-पानी की ताकत

पर्याप्त लैंड बैंक, भूमि, सरप्लास बिजली, जल संसाधन और ग्रीन एनर्जी की उपलब्धता को निवेश की बड़ी ताकत बताया।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 6 से 8 सितंबर का दुबई दौरा मध्यप्रदेश की निवेश रणनीति को वैश्विक मंच पर नए विस्तार देने वाला रहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मंशा निवेश के साथ तकनीक, बाजार, निर्यात और रोजगार को जोड़कर मध्यप्रदेश को वैश्विक निवेश एवं विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाना है। एआईएम काग्रेस-2026 में मुख्यमंत्री डॉ यादव ने मध्यप्रदेश को केवल निवेश के गंतव्य के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक कंपनियों और निवेशकों के लिए दीर्घकालिक साझेदार के रूप में प्रस्तुत किया। दुबई प्रवास के दौरान लगभग 53 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यूएई के शीर्ष मंत्रियों, तातारस्तान के नेतृत्व, विश्व बैंक और डीपी वर्ल्ड, क्रिसैट एंटरप्राइज, जेम्स एजुकेशन, शराफ ग्रुप, चोइथराम्स, राणा होल्डिंग्स, वीएफएस ग्लोबल और ऋषभ ॥ जैसी कंपनियों के साथ हुई बैठकों में लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, एआई एवं डिजिटल टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, ई-मोबिलिटी, फार्मा, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, आधुनिक विनिर्माण और वेस्ट-टू-एनर्जी जैसे क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी की संभावनाएं खुलीं। दुबई ने मध्यप्रदेश में पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने, विमानन संपर्क बढ़ाने तथा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 में उच्चस्तरीय निवेशक दल के साथ भागीदारी की दिशा में सहमति जताई, वहीं विश्व बैंक ने एआई और डिजिटल गवर्नेंस परियोजनाओं में सहयोग में रुचि दिखाई।

एमपी में 7500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती

गृह जिले में पोस्टिंग नहीं, चुनी यूनिट में 5 साल रहना होगा; 22 सितंबर से कर सकेंगे आवेदन

आरक्षक (जीडी) – कुल 7,500 पद

आरक्षक (सामान्य झूटी) – विशेष सशस्त्र बल: 700 पद

आरक्षक (सामान्य झूटी) – विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर: 6,800 पद

भोपाल। मध्यप्रदेश में 7,500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल ने शेड्यूल जारी किया है। आवेदन 22 सितंबर से शुरू होंगे और 6 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को गृह जिले में पदस्थापना नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन के दौरान प्रदेश के 55 जिलों में अपनी यूनिट चुननी होगी।

जिस यूनिट में नियुक्ति मिलेगी, वहां कम से कम 5 साल की सेवा पूरी करना जरूरी होगा। इसके बाद ही दूसरी यूनिट में ट्रांसफर किया जा सकेगा। अभ्यर्थी को आवेदन में यह भी स्पष्ट करना होगा कि वह आरक्षक (एसएफएफ को छोड़कर) या आरक्षक विशेष सशस्त्र बल के पद के लिए आवेदन कर रहा है। चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति शासकीय रेल पुलिस इंदौर, जबलपुर और भोपाल में भी की जाएगी। परीक्षा केंद्र पर आधार-इनेबल्ड बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा होने पर अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा।

कच्चा तेल 100 डॉलर पार



6 हफ्ते में सबसे महंगा. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने का असर, पेट्रोल-डीजल और एलपीजी महंगी हो सकती है

मुंबई। कच्चे तेल यानी क़रूड ऑयल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। आज यानी 9 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेट क़रूड के दामों में 2.25 प्रतिशत का इजाफा हुआ। इसकी वजह अमेरिका-ईरान के बीच फिर तनाव बढ़ना बताया जा रहा है। इस बढ़ोतरी के पहले क़ूड की कीमत 98 बैरल प्रति डॉलर थी। इससे पहले 24 जुलाई को क़रूड का दाम 100 बैरल प्रति डॉलर पहुंचा था। अगर कच्चे तेल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो इससे पेट्रोल-डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ सकते हैं।

कैबिनेट के फैसले रेलवे के सात हाई-डेंसिटी कॉरिडोर होंगे फोर-ट्रैक

सात हाई-डेंसिटी कॉरिडोर पर क्या होगा काम

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे के पूर्ण ओवरहाल और आधुनिकीकरण की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके तहत सात हाई-डेंसिटी रेलवे कॉरिडोर को फोर-ट्रैक और क्वाड्रपल करने की योजना है। इन कॉरिडोर पर ट्रैक क्षमता बढ़ाने का काम किया जाएगा, ताकि भविष्य में इन मार्गों पर बढ़ने वाले यातायात का दबाव संभाला जा सके।

गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और उसके दोनों डायगोनल पर बढ़ेगी क्षमता

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के हाई-डेंसिटी कॉरिडोर को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली-मुंबई, मुंबई-चेन्नई, चेन्नई-कोलकाता और कोलकाता-दिल्ली मार्ग मिलकर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली-चेन्नई और मुंबई-कोलकाता इसके दो डायगोनल हैं। इसके अलावा दिल्ली-गुवाहाटी कॉरिडोर भी इस योजना में शामिल है। इस तरह कुल सात हाई-डेंसिटी कॉरिडोर को क्वाड्रपल यानी चार-लेन किया जा रहा है। वैष्णव के मुताबिक, इन सभी परियोजनाओं पर चरणबद्ध तरीके से काम आगे बढ़ रहा है। फिलहाल करीब 4,000 किलोमीटर के हिस्से के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। कैबिनेट समिति ने बुधवार को रेलवे मंत्रालय की तीन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी।

मोहन सरकार ने मानी बात: इंटर्न डॉक्टरों की मांग पर बड़ी फैसला अब 21500 रु. मिलेंगे,आंदोलन खत्म काम पर लौटे; लाठीचार्ज-वाटर कैनन मामले में 2 पुलिसकर्मी लाइन

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने तीन दिन से जारी इंटर्न डॉक्टरों के प्रदर्शन के बाद उनके स्ट्राइक में 7,000 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। अब प्रदेश के इंटर्न डॉक्टरों को हर महीने 21,500 रुपये स्ट्राइक दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत के बाद इस बढ़ोतरी पर सहमति बनी। इससे पहले इंटर्न डॉक्टर 14,337 रुपये के मासिक स्ट्राइक को बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की मांग कर रहे थे।

स्ट्राइक बढ़ाने पर बनी सहमति

अपनी मांगों को लेकर इंटर्न डॉक्टरों ने सोमवार को भोपाल के हर्मीदिया अस्पताल के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कथित तौर पर लाठीचार्ज भी किया गया। कार्रवाई में कई डॉक्टरों के घायल होने की बात सामने आई थी। घटना के बाद डॉक्टरों में आक्रोश बढ़ गया। मामले का संज्ञान लेते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जांच के निर्देश दिए।

ओपीडी बंद होने से बढ़ा सरकार पर दबाव

स्ट्राइक बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे इंटर्न डॉक्टरों, जूडा और एमटीए के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से चर्चा की। बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री के दुबई दौरे से लौटने के बाद स्ट्राइक बढ़ाने की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। इसी बीच इंटर्न डॉक्टरों के समर्थन में मध्यप्रदेश डॉक्टर महासंघ ने बुधवार को प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद रखने का आह्वान किया। ओपीडी बंद रहने से सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचे इससे सरकार पर आंदोलन का जल्द समाधान निकालने का दबाव बढ़ गया।

आईआरजीसी ने दी पलटवार। अमेरिका ने खार्ग द्वीप के पास मिसाइल हमले में उड़ाए ईरान के पांच तेल टैंकर

तेहरान, एजेंसी

अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध अभी भी जारी है। अमेरिका ने मंगलवार, 8 सितंबर को फारस की खाड़ी में खार्ग द्वीप के पास ईरान के कई तेल टैंकरों पर हमला किया। सेंट्रल कमांड ने 8 सितंबर को ईरान के कच्चे तेल ले जाने वाले जहाजों के नष्ट करने का सैटेलाइट वीडियो भी जारी किया। अमेरिकी कार्रवाई पर हमला होने के बाद अमेरिकी सेना ने ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया।

आईआरजीसी ने अमेरिका के युद्धपोत को बनाया निशाना

मिडिल ईस्ट में ये हमले सिर्फ अमेरिका की तरफ से जारी नहीं हैं। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स ने पिछले दो दिनों में दो बार बैलिस्टिक मिसाइलों से रनौसेना के युद्धपोत को निशाना बनाया। रनौसेना के युद्धपोत ने ईरान के दोनों मिसाइल हमलों से खुद को बचाया और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में गरत जारी रखी, लेकिन अमेरिकी सेना ने हमलों का जवाब

दिया और ईरान के तेल टैंकरों को उड़वा।

अमेरिकी सेना ने जारी की सैटेलाइट तस्वीरें

सेंट्रल कमांड ने ईरानी तेल टैंकरों पर हमले के बाद बताया कि अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरान के कच्चे तेल ले जाने वाले जहाजों कविज, चारमीनार, होराजन 1 और रिस्को को और खार्ग द्वीप के पास डेवों को नष्ट कर दिया। अमेरिकी सेना का दावा है कि ईरान ने आईआरजीसी और उसके क्षेत्रीय

जवाब में ईरान ने जॉर्डन पर किया हमला

आईआरजीसी ने बुधवार को कहा कि तेहरान के जहाजों पर अमेरिकी हमलों के जवाब में उन्होंने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइलों से हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक, गाइड्स ने एक ऑपरेशन के तहत जॉर्डन में अमेरिकी अल-अजराक बेस पर भारी मिसाइल हमले किए। वहीं जॉर्डन का कहना है कि उसने ईरान से आई 20 में से 18 मिसाइलों को मार गिराया। सरकारी न्यूज एजेंसी ने बुधवार को सेना के हवाले से बताया कि दो मिसाइलें सुनसान इलाकों में गिरीं और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

फ्रॉक्सी समूहों को फंड देने के लिए अरबों डॉलर के शैडो नेटवर्क के हिस्से के रूप में इन टैंकरों का इस्तेमाल किया था। संटकाम ने 5 सितंबर को भी ईरान के तीन कच्चे तेल के जहाजों को नष्ट किया था अमेरिका ने कहा कि पहले के हमले ईरान द्वारा यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर और गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर हमले की कोशिश के बाद किए गए थे।

14 से 16 सितंबर तक घरेलू उद्योग को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका पोखरण रेंज में ‘ड्रोनथॉन’ दिखाएगा स्वदेशी ऑपरेशनल क्षमता

नई दिल्ली (एजेंसी)

घरेलू उद्योग को अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स (यूएएस) और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स (सीयूएएस) में अपनी काबिलियत और तरक्की दिखाने के लिए भारतीय वायु सेना 14 से 16 सितंबर तक जैसलमेर के पोखरण रेंज में ‘आईएफएफ ड्रोनथॉन’ का आयोजन करने जा रही है। यह इवेंट नई ड्रोन और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ-साथ उनकी ऑपरेशनल क्षमता देखने और आपसी सीख को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। रक्षा मंत्रालय का

कहना है कि इस इवेंट में स्थिर और लाइव प्रदर्शन शामिल है। इसमें सर्विलांस और टोही, ऑटोनॉमस ऑपरेशन, ड्रुड टेक्नोलॉजी और

भारतीय वायुसेना में ‘ड्रोनथॉन’ इंडस्ट्री, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी डेवलपर्स को एक साथ लाएगा, ताकि वे अनमैन्ड और काउंटर-अनमैन्ड सिस्टम में अपनी काबिलियत दिखा सकें। तीन दिन के इस इवेंट में वायुसेना सर्विलांस और रिकॉनसेंस, ऑटोनॉमस ऑपरेशन, स्वर्गम टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एप्लीकेशन में परफॉर्मंस का मूल्यांकन करेगी। सरकार की यह पहल भारत के आत्मनिर्भर भारत के मकसद से जुड़ी है, जिसका मकसद घरेलू डिफेंस की क्षमता बढ़ाना है। वायुसेना ने ‘ड्रोनथॉन’ को अनमैन्ड सिस्टम में तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए तैयार किया है, जहां ऑपरेशनल डिमांड पारंपरिक एविएशन टाइमलाइन की तुलना में तेजी से बदल रही है। खासतौर पर काउंटर-ड्रोन कैपेबिलिटी सभी सेनाओं में प्रायोगिक से परिचालन प्राथमिकता तक में बदल गई है, जो रीजनल थिएटर्स में दुश्मन ड्रोन एक्टिविटी के बढ़ने को दिखाती है।

इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय विजन के साथ तालमेल बिठाते हुए ड्रोनथॉन-2026 का

मकसद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, स्टार्ट-अप और इनोवेटर्स को जोड़कर स्वदेशी डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत करना है।

निजी निर्माता की भूमिका

सेनाओं में हाल की पहलों ने ड्रोन लॉजिस्टिक्स डिजिटायजेशन से लेकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर पर स्टैंडऑफ वेपन इंटीग्रेशन तक प्राइवेट मैनुफैक्चरर्स की भूमिका को बढ़ाया है। ड्रोनथॉन से वायुसेना को टैडिशनल प्रोद्योरमेंट की तुलना में तेजी से समाधान पहचानने में मदद मिलेगी। यह इवेंट रक्षा मंत्रालय के स्वदेशी ड्रोन इंडस्ट्रियल बेस बनाने की प्रतिबद्धता का भी संकेत देता है, जिससे गोला-बारूद प्रोक्वायन, मिसाइल सिस्टम और एडवांस्ड प्लेटफॉर्म पर सेनाओं और घरेलू डिफेंस फार्मों के बीच चल रही पार्टनरशिप और मजबूत हुई है।

रुद्राभिषेक कार्यक्रम में पहुंची थीं। यहां उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे के बयान को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में ये बात कही। राण ने नवरात्रि में गरबा आयोजनों में मुस्लिमों की एंट्री का विरोध किया था।

महाराष्ट्र सीएम की पत्नी बोलीं- त्योहार का शांतिपूर्वक आनंद लेने में क्या बुराई

गणेशोत्सव में डीजे को लेकर कहा-आसपास के लोगों को परेशानी न हो

अमृता फडणवीस ने गणेशोत्सव के दौरान डीजे और तेज संगीत को लेकर चल रहे विवाद पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि त्योहार मनाते समय सभी को सरकार और अदालतों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि हमारे उत्सवों के कारण समाज या क्षेत्र के अन्य नागरिकों को कोई परेशानी न हो। घर पर यथासंभव धर्म का पालन करना अच्छा है।

संक्षिप्त समाचार

जन शिक्षण संस्थान में प्रमाण पत्रों का वितरण

सतना। कौशल विकास एवम उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित जन शिक्षण संस्थान सतना के केंद्र उद्घाटन में गत

सत्र 2025-26 में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान के निदेशक राजकुमार सनाहय के निर्देशन में ब्यूटी कैयर असिस्टेंट और सॉफ्ट टॉयज मेकिंग प्रशिक्षणों के प्रमाण पत्रों का वितरण संस्थान के कार्यक्रम अधिकारी वा ब्लॉक प्रभारी प्रदीप कुमार जैन व 08 सितंबर को किये गया। साथ ही ब्यूटी कैयर असिस्टेंट प्रशिक्षण की परीक्षा भी संपन्न कराई गई। इस अवसर पर ट्रेनर मीरा चौरसिया वा पुष्पा चौरसिया, शिक्षिका मीरा गर्ग व प्रशिक्षणार्थी गण उपस्थित रही। उल्लेखनीय है कि जन शिक्षण संस्थान द्वारा संपूर्ण जिले में संचालित किए जा रहे विभिन्न स्वरोजगारणमुखी प्रशिक्षणों का लाभ जरूरत मंद महिलाओं पुरुषों को कि कम पढ़े लिखे हैं, स्कूल ड्रॉप आउट हैं रुझिमेंट्री स्तर के हैं , के द्वारा प्राप्त करके स्वयं का केंद्र ,रोजगार स्थानीय स्तर पर स्थापित कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और आसानी के अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हो रहे हैं।



शहर में शुरू हुई गणेशोत्सव की तैयारियां

नगर संवाददाता, सतना।

भगवान गणेश सभी देवी-देवताओं में प्रथम पूजनीय हैं। विवाह की अग्नि प्रज्वलित होने से पहले, नई दुकान खुलने से पहले या बहीखाते पर पहला पन्ना लिखे जाने से पहले भगवान गणेश का नाम लिया जाता है। वे विघ्नहर्ता हैं, जो बाधाओं को दूर करने वाले हैं। भाद्रपद माह के दस दिनों तक वे सिर्फ हमारी प्रार्थनाएं ही पूरी नहीं करते बल्कि वे धरती पर निवास

करते हैं। इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर सोमवार से शुरू होगा। गणेशोत्सव को लेकर शहर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। मूर्तिकारों ने गणेश प्रतिमाओं को सजाने व संचारने का काम शुरू कर दिया है तो वहीं रेडिमेड प्रतिमाओं के लिए दुकाने लगाने का काम जारी है। वहीं सजावट आदि के सामानों की नई -नई वैरायटी दुकानों में उपलब्ध कराने का काम दुकानदार कर रहे हैं।

कितने दिन बाद कर सकेंगे विसर्जन

हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से देशभर में गणेश उत्सव का शुभारंभ होता है। इस दिन को भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि, इस शुभ अवसर पर, भक्तजन अपने घर गणपति जी को लाते हैं और विधि-विधान से उनकी पूजा-अर्चना करते



तिथि व स्थापना मुहूर्त

हिंदू पंचांग के मुताबिक, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। अधिकांश हिंदू व्रत सूर्योदय के समय ही किए जाते हैं लेकिन गणेश स्थापना दोपहर के समय की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि भगवान गणेश का जन्म दोपहर में ही हुआ था। दोपहर के समय मूर्ति स्थापित करना काफी शुभ माना जाता है।पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथि का आरंभ 14 सितंबर 2026 को सुबह 7 बजकर 6 मिनट पर होगा और इसका समापन 15 सितंबर को सुबह 7 बजकर 44 मिनट पर होगा। उदया तिथि के अनुसार, गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर 2026, सोमवार को ही मनाया जाएगा। इसी दिन गणपति जी की स्थापना की जाएगी। गणेश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11.02 बजे से दोपहर 1.31 बजे तक रहेगा।

मुहूर्त पर नजर...

गणेश चतुर्थी प्रारंभ- सोमवार, 14 सितंबर सुबह 7 बजकर 6 मिनट
चतुर्थी तिथि समाप्त - मंगलवार 15 सितंबर सुबह 7 बजकर 44 मिनट

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन



नगर संवाददाता, सतना।

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के तत्वाधान में ब्लॉक व तहसील अध्यक्ष सोहावल द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव मप्र शासन भोपाल के नाम ज्ञापन मंगलवार 8 सितम्बर को अनुविभागीय अधिकारी रघुजैननगर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मुख्यमंत्री की घोषणाओं कर्मचारियों पेंशनरों के स्वास्थ्य बीमा योजना, कर्मचारी

आयोग का गठन, एवं दो संतान की बाध्मता समाप्ति, करने संबंधित अपेक्षित कार्यवाही, लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान ओपीएस बहाली, स्ट्राइपेंड समाप्ति, सहित अन्य मांगों ज्ञापन में दिया गया।

मप्र राज्य कर्मचारी संघ के ब्लॉक अध्यक्षविष्णु नारायण त्रिपाठी तहसील अध्यक्ष हेमराज सिंह के नेतृत्व में समस्त पदाधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिनमें मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष जितेंद्र त्रिपाठी, संतोष श्रीवास्तव, ऋषिकेश गुप्ता, विजय सिंह परिहार, हेमराज सिंह, अमित त्रिपाठी, रमेश चतुर्वेदी, अमित मिश्रा, प्रह्लाद वर्मा, सुरेंद्र रावत, प्रियव्रत सिंह, राजेन्द्र सिंह, सूर्यप्रकाश चौधरी, शोभा चौधरी, सरला तिवारी,प्रवीण मिश्रा, सूरज मिश्रा, शशिलता धुवें, सेहलता खरे, खुशबू सिंह, किरण सिंह, विवेक प्रजापति, अजीत सिंह, कमलेंद्र सिंह, संध्या मिश्रा, साधना शुक्ला, रघु, राजकुमारी शुक्ला, संजीव गर्ग, भूपेंद्र सिंह, पुष्पा सिंह, पुष्पा कुशवाहा, सोरभ सिंह, अजय सिंह, कामिनी गौतम, नवाब सिंह, पंकज सिंह, विनीत धुवें, अखिला सेन आदि उपस्थित रहे।

माटी गणेश-सिद्ध गणेश अभियान अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन



नगर संवाददाता, सतना।

मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वावधान में माटी गणेश-सिद्ध - गणेश अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन विनायक पब्लिक स्कूल, पौराणिक टोला में किया गया। कार्यक्रम में माटी से निर्मित गणेश प्रतिमा के उपयोग तथा पर्यावरण

हितैषी गणेशोत्सव मनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आशीष कुमार ताम्रकार जिला समन्वयक, सुभाष चौधरी जिला विधिक अधिकारी, अरुण सिंह ब्लॉक समन्वयक, विश्वनाथ ब्लॉक समन्वयक, राम नारायण त्रिपाठी, प्रेमशंकर भनेश, परामर्शदाता अर्चना त्रिपाठी, श्रद्धा दुबे, अनिल त्रिपाठी सहित विद्यालय परिवार एवं अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे।

महर्षि कश्यप ऋषि जयंती व वैश्य दिवस की तैयारी

■ वाहन रैली, प्रभात फेरी व शोभायात्रा के लिए बनी कार्ययोजना

नगर संवाददाता, सतना।

महर्षि कश्यप ऋषि जयंती एवं वैश्य दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक कश्यप मैरिज गार्डन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वैश्य परिषद अध्यक्ष कमलेश गुप्ता ने की, जबकि कार्यक्रम संयोजक हरिओम गुप्ता की उपस्थिति में कार्यक्रम का रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम मीडिया संयोजक महेश कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में 14 सितंबर को आयोजित होने वाली वाहन रैली तथा 15 सितंबर को होने वाली प्रभात फेरी एवं शोभायात्रा की तैयारियों को लेकर सघन विचार-विमर्श किया



गया।कार्यक्रम संयोजक हरिओम गुप्ता ने तैयारियों से संबंधित जानकारी दी। बैठक का संचालन वैश्य परिषद के उपाध्यक्ष विनोद गुप्ता ने किया।

शहर के विभिन्न मार्गों से 14 को निकलेगी वाहन रैली

बैठक मे चर्चा हुई कि 14 सितंबर को दोपहर 3 बजे विशाल वाहन रैली वैश्य घटकों के युवा साथियों एवं मातृशक्ति की सहभागिता से हनुमान नगर, नई बस्ती से हरी झंडी दिखा कर प्रारंभ होगी। वाहन रैली शहर के विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए टिकुरिया

को लेकर बैठक

भ्रमण करते हुए कसौधन धर्मशाला, केशव दास मंदिर, पुराना पावर हाउस चौक पहुंचेगी, जहां प्रसाद वितरण के साथ शोभायात्रा का समापन होगा।

ये रहे मौजूद

टोला स्थित कश्यप चौक पहुंचेगी, जहां स्वल्पाहार के साथ रैली का समापन होगा।

15 को निकाली जायेगी शोभायात्रा

वहीं 15 सितंबर, ऋषि पंचमी के अवसर पर टिकुरिया टोला कश्यप चौक स्थित महर्षि कश्यप ऋषि के मंदिर में दोपहर 1 बजे पूजा-अर्चना एवं मंचीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके पश्चात दोपहर 3 बजे टिकुरिया टोला स्थित गुरुकुलम स्कूल के पास से भव्य शोभायात्रा प्रारंभ होगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से

भ्रमण करते हुए कसौधन धर्मशाला, केशव दास मंदिर, पुराना पावर हाउस चौक पहुंचेगी, जहां प्रसाद वितरण के साथ शोभायात्रा का समापन होगा।

ये रहे मौजूद

बैठक में प्रमुख रूप से जगदीश गुप्ता, कमलेश गुप्ता, हरिओम गुप्ता, विनोद गुप्ता, घनश्याम केसरी, अशोक कुमार गुप्ता, श्याम सुंदर गुप्ता, रामजी गुप्ता, जगदीश गुप्ता, सचिन गुप्ता, गणेश प्रसाद गुप्ता, छवी गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, सी.एल. गुप्ता, सतीश गुप्ता, अजय गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता, अश्विनी गुप्ता, जयप्रकाश गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, देवीदिन गुप्ता, विकास गुप्ता, दयाल दास गुरु, महेश कुमार गुप्ता, आशीष गुप्ता एवं बेदू गुप्ता समेत भारी संख्या में वैश्य समाज के सामाजिक बंधु उपस्थित रहे।

नेकी फाउंडेशन ने किया महाआरती का आयोजन



नगर संवाददाता, सतना।

प्रत्येक महीने की तरह इस बार भी दक्षिण मुखी हनुमान जी पुरानी कचहरी में जन कल्याण के लिए देव हनुमान जी के चरणों में विनय आरती की गई। आरती के प्रारंभ में पंडित ओंकार परासी द्वारा मंत्र उच्चारण कर अतिथियों से दीपक प्रजलित कराए गए। इस महा आरती में नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी वरिष्ठ समाजसेवी मनमोहन मोहेश्वरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। धीरज एवं संस्था के वृजेश शुक्ला ने सभी भक्त जनों का तिलक वंदन कर अभिनंदन

किया। इसी के साथ अंशुल तिवारी, मोहित सिंह कपूर , डॉ राहुल मेहरोत्रा सहित मातृ शक्तियों में निधि कपूर,गुरुशा सिंह कपूर,शालिनी सिंह, डॉ रिकल मेहरोत्रा ,विक्रम माकीन एवं काफी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। जन कल्याण के लिए की जाने वाली यह महा आरती विगत कई वर्षों से निरंतर जारी है। यही कारण है कि भक्तों की भीड़ निरंतर बढ़ रही है। संस्था के संस्थापक राजेंद्र सिंह कपूर ने सभी भक्तों का अभिनंदन करते हुए जनकल्याण के लिए देव चरणों में दुआएं मांगी।

[मौसम] 4 दिन में 7 डिग्री बढ़ा पाता

थमी बारिश, बढ़ी उमस व गर्मी

नगर संवाददाता, सतना।

पिछले कुछ दिनों से जिले में बारिश लगभग थम सी गई है। आसमान में रह रहकर बादल डेरा डाल रहे हैं लेकिन बारिश नहीं होने से एक बार फिर से उमस व गर्मी का असर देखने को मिलने लगा है। मंगलवार को बादलों के बीच सूर्यदेव की लुकाछिपी कई बार देखने को मिली। हल्की बूंदबांदी के बाद जैसे ही धूप निकली गर्मी व उमस से लोग बेहाल होने लगे।

अब तक 1251.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

जिले में इस वर्ष 1 जून से 8 सितम्बर तक 1251.9 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई



है। अधीक्षक भू-अभिलेख सतना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले की सतना (रघुराजनगर) तहसील में 1353.4 मि.मी., सोहावल (रघुराजनगर) में 1307 मि.मी., बरौंथा (मझगांव) में 1568.8 मि.मी., बिरसिंहपुर में 1418.4 मि.मी., रामपुर बाघेलान में 1331

मि.मी., नागौद में 1299.7 मि.मी., जसो (नागौद) में 853.7 मि.मी. एवं उचेहरा में 883 मि.मी. औसत वर्षा अब तक दर्ज की जा चुकी है। जिले की औसत सामान्य वर्षा 891.7 मि.मी. है। विगत वर्ष इस अवधि तक जिले में औसत वर्षा 982.7 मि.मी. वर्षा दर्ज की जा चुकी थी।

तापमान पर एक नजर		
दिनांक	अधिकतम	न्यूनतम
5 सितम्बर	26.6	24.0
6 सितम्बर	29.7	24.7
7 सितम्बर	31.4	24.6
8 सितम्बर	33.0	25.0
(नोट : तापमान डिग्री सेल्सियस में)		

33 डिग्री पर पहुंचा अधिकतम पारा

बारिश थमने के बाद से तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी हो गया है। चार दिन पहले शनिवार को अधिकतम तापमान जहां 26.6 डिग्री रिकार्ड किया गया था वहीं चार दिन बाद मंगलवार को 33.0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इसी प्रकार से न्यूनतम तापमान जो शनिवार को 24.0 डिग्री सेल्सियस था उसमें मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।

‘विश्व हृदय दिवस’ पर विशेष पोस्टर का विमोचन



सतना। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं भारत विकास परिषद सतना के संयुक्त तत्वावधान में ‘विश्व हृदय दिवस’ के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर आज पोस्टर का विमोचन किया गया। आयोजकों ने बताया कि ‘दिल की बातें, हम भी जाने’ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में देश के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञों द्वारा हृदय स्वास्थ्य, हृदय रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवनशैली को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी एवं मार्गदर्शन दिया जाएगा। यह कार्यक्रम रविवार, 27 सितंबर को शाम 4 बजे से 6 बजे तक टाउन हॉल, सेमरिया चौक में आयोजित होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को हृदय रोगों के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

चेम्बर ने प्रभारी मंत्री को शहर की दुर्दशा से कराया अवगत

नगर संवाददाता, सतना।

प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सतना प्रवास के दौरान चेम्बर अध्यक्ष श्री सतीश सुखेजा के नेतृत्व मे चेम्बर प्रतिनिधि मण्डल ने सर्किट हाउस मे प्रभारी मंत्री से मुलाकात की। चेम्बर महामंत्री मनोज कटारे ने बताया कि चेम्बर अध्यक्ष द्वारा शहर की जर्जर सड़के, गंदे पानी के निकास की समस्या, यातायात की समस्या, ठेलों के अतिक्रमण के कारण उत्पन्न अव्यवस्था से प्रभारी मंत्री को अवगत कराया। चेम्बर अध्यक्ष ने मुलाकात के दौरान 1 जुलाई 2026 से लेकर अभी तक शासन के साथ किये गये सभी पत्राचारों की प्रतिलिपि एवं शहर की समस्याओं पर 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए यह भी बताया कि चेम्बर ने 14 जुलाई 2026 को शहर की मूलभूत सुविधाओं के



प्रति नगर निगम की उदासीनता के विरोध मे नगर निगम का घेराव किया था और शहर के व्यापारी लगभग 6 घण्टे तक नगर निगम कार्यालय के बाहर जमीन पर बैठकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते रहे परन्तु नगर निगम आयुक्त मौके पर नहीं पहुंचे उनके स्थान पर महापौर ने चेम्बर का ज्ञापन स्वीकार करते हुए यह कहा था कि चेम्बर की मांगे जायज हैं और यह आश्वासन भी दिया था कि तीन दिन के अंदर

व्यापारियों के प्रतिनिधि मण्डल के साथ एक वृहद बैठक कर समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जायेगा परन्तु दुर्भाग्य है कि आज दिनांक तक महापौर एवं नगर निगम अमले द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और शहर की हालात बढ़ रहे हैं। प्रभारी मंत्री ने चेम्बर अध्यक्ष को यह आश्वासन दिया है कि अधिकारियों को निर्देशित कर समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जायेगा।

संक्षिप्त समाचार

महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजयलक्ष्मी हुई गंभीर बीमार



रीवा। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष ग्रामीण विजय लक्ष्मी मिश्रा अचानक गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गई हैं। बताया गया कि विजय लक्ष्मी महिला कांग्रेस के इंदौर स्नेह बंधन रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल हुईं, इसके बाद राहुल गांधी के 19 सितंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारी बैठक में शामिल होने के बाद इंदौर से रीवा आने पर उनको अचानक ही चक्कर मार दिया इसके बाद वह गंभीर रूप से बीमार हो गई हैंजिनका इलाज भगवती अस्पताल न्यूरोसर्जन डॉक्टर दिनेश पटेल के सान्निध्य में चल रहा है।

कमिश्नर आज करेंगे विभिन्न विभागों की समीक्षा

रीवा। संभाग के कमिश्नर शीलेन्द्र सिंह 9 सितम्बर को शाम 4 बजे से वीडियो कॉफ़रिंग के माध्यम से आयोजित संभागीय बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। बैठक में राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पुलिस एवं आबकारी विभाग से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करेंगे। सभी संबंधित अधिकारियों को 8 सितम्बर तक एजेण्डा बिन्दुओं की जानकारी प्रस्तुत करने तथा बैठक में वीडियो कॉफ़रिंग से बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। संभागीय अधिकारी कमिश्नर कार्यालय एनआईसी केन्द्र से बैठक में शामिल होंगे।

बाल भारती विद्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया शिक्षक दिवस



रीवा, नगर संवाददाता। 05 सितम्बर 2026 को बाल भारती विद्यालय में शिक्षक दिवस समारोह डॉ. अमोल कुमार मिश्रा 'बटरोही' सेवानिवृत्त पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी के मुख्यातिथि में सम्पन्न हुआ। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि डॉ. मिश्रा जी ने पूर्व राष्ट्रप्रति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया। विद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा पुष्पगुच्छ भेंटकर 'हे गुरुवर तुम्हीं ने राह दिखाई' स्वागत गीत के माध्यम से मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य ने मुख्य अतिथि का परिचय देते हुए अपने स्वागत भाषण में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन एवं उनके शिक्षा के प्रति योगदान को याद करते हुए कहा कि 'शिक्षक केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि विद्यार्थियों को जीवन जीने की कला भी सिखाता है।' शिक्षक किसी भी राष्ट्र का शिल्पी होता है। उस पर राष्ट्र की बड़ी जिम्मेदारी होती है। वह बच्चों में चरित्र निर्माण एवं नैतिक कर्तव्यों को विकसित कर सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। विद्यालय कैप्टन मास्टर अक्षत त्रिपाठी ने गुरुजनों को शत-शत नमन करते हुए राष्ट्रोत्थान एवं समाज कल्याण में शिक्षकों के योगदान को सर्वोपरि बताया।

समीक्षा बैठक में कमिश्नर का निर्देश अनुपस्थिति पर पैरा स्टाफ के विरुद्ध होगी कार्रवाई

रीवा, नगर संवाददाता। संभाग के कमिश्नर श्री शीलेंद्र सिंह ने संभागीय समय सीमा की बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि गत दिनों हुई लगातार बारिश के दौरान जो शासकीय संपत्ति डैमेज हुई है, सभी संबंधित विभाग प्रमुख अपनी शासकीय संपत्तियों को हुए नुकसान का आकलन करें और सभी शासकीय संपत्तियों एवं भवनों को पुनः रिस्टर करें। इसके लिए व्यापक स्तर पर प्लान बनाकर मेरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दें।

कमिश्नर ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपनी शासकीय परिसंपत्तियों पर हुए अतिक्रमण को पुलिस विभाग के सहयोग से तत्काल हटाना सुनिश्चित करें एवं कब्जाधारियों के विरुद्ध अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज कर



कार्रवाई करें। कमिश्नर ने 100 दिवस से अधिक की सीएम हेल्पलाइन की सभी शिकायतों का आगामी एक सप्ताह में निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान कमिश्नर ने महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, खाद्य विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, श्रम विभाग, विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपनी 100 दिवस से अधिक की शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण करना सुनिश्चित करें।

कमिश्नर ने कहा कि शिकायतों के निराकरण में लापरवाही एवं देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर ने निर्देश दिए की सभी चिकित्सालयों में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ अपनी निर्धारित ड्यूटी नियम एवं ईमानदारी से करना सुनिश्चित करें। यदि कोई चिकित्सक या पैरामेडिकल स्टाफ नियम विरुद्ध ड्यूटी से अनुपस्थित पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध प्रभावशील कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि चिकित्सालय में इलाज कराने आए मरीज के एक अटेंडर

को ही रहने की अनुमति दी जाएगी। कमिश्नर ने स्कूल शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह जिलों में नीट एवं जेडई के प्रश्न बैंक बनवाएं ताकि विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। उन्होंने संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा को निर्देश दिए की सभी महाविद्यालय एवं विकासखंड में स्थित महाविद्यालयों में यूपीएससी एवं एमपीपीएससी की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित करते रहें एवं विद्यार्थियों को विषय से

संबंधित सभी पाठ्यक्रम एवं सिलेबस उपलब्ध कराया जाए। मेडिकल कॉलेज के प्रभारी डीन डॉ. मनोज इंदुरकर ने बताया कि संजय गांधी अस्पताल में मरीज के अटेंडर की संख्या एक रखी जाएगी एवं अस्पताल में एक एंट्री पॉइंट ही रखा जाएगा। मोबाइल टीम बनाई गई है, आपातकालीन स्थिति में इंटरकॉम फोन के माध्यम से ही चिकित्सक आपस में संपर्क में रहेंगे। कमिश्नर ने प्रभारी डीन को निर्देश दिए कि वह अस्पताल में हुए क्रिटिकल उपचार एवं ऑपरेशन तथा अच्छे कार्यों की स्टोरी मीडिया एवं आम जनता से साझा करें। बैकव में संयुक्त आयुक्त वीरेंद्र पटेल, उपायुक्त राजस्व एलएल अहिरवार, डिप्टी कमिश्नर श्रीमती दिव्या त्रिपाठी सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारी गण उपस्थित रहे।



रीवा, नगर संवाददाता। रीवा कलेक्टर कार्यालय के सामने 8 सितंबर 2026 से नगरवासियों द्वारा धरना एवं हनुमान चालीसा पाठ शुरू किया गया है। यह आयोजन 'सद्बुद्धि दो राम' के नाम से किया जा रहा है। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा कल्पना मिश्रा प्रकरण में उचित कार्रवाई करते हुए उनकी

मांगों को पूरा किया गया था, जिसके बाद भी अनशन जारी है और नई मांगें रखी जा रही हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस नेताओं के दबाव के कारण अनशन समाप्त नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर नगरवासी राजेंद्र शुक्ल के समर्थन में धरना दे रहे हैं और हनुमान चालीसा पाठ एवं व्याख्यान माला का आयोजन कर रहे हैं।

ग्रीन बेल्ट में निर्मित स्थाई स्ट्रक्चर पर होगी कार्यवाही

■ सर्वे के आधार पर जारी होंगे नोटिस

रीवा, नगर संवाददाता। निगम आयुक्त अक्षत जैन द्वारा शहर के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में निर्मित स्ट्रक्चर के संबंध में समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि सर्वे कराकर नियमानुसार 50 मीटर के दायरे में आने वाले समस्त स्थाई स्ट्रक्चर को नोटिस जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि सर्वे कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए तथा नियमों के विपरीत पाए गए निर्माणों पर नियमानुसार आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

निगम आयुक्त ने भवन अनुज्ञा से संबंधित कार्यों को और अधिक व्यवस्थित बनाने हेतु बिल्डिंग इंस्पेक्टर एवं बिल्डिंग ऑफिसर की विशेष ट्रेनिंग आयोजित कराने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण में मास्टर प्लान, भूमि विकास नियम एवं



भवन अनुज्ञा से जुड़े समस्त प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी, ताकि समस्त अनुज्ञाएं नियमों का पूर्ण पालन करते हुए जारी हों और भविष्य में भवन अनुज्ञा को लेकर किसी प्रकार की समस्या की स्थिति निर्मित न हो। आयुक्त ने कहा कि प्रशिक्षण उपरांत भवन अनुज्ञा की प्रक्रिया में एकरूपता आएगी तथा आवेदकों को भी अनावश्यक विलंब का सामना नहीं करना पड़ेगा। नियमानुसार प्राप्त आवेदनों का

निराकरण निर्धारित समय-सीमा में किया जाए यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर मौके पर उपस्थित रहकर स्थल निरीक्षण करें एवं अपनी रिपोर्ट प्रकरण में अनिवार्य रूप से संलग्न करें। निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि इस कार्य में लापरवाही बरतने पर तथा नियमों को दखिनार कर अनुज्ञा जारी किए जाने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

युकां पर आंसू गैस और पानी की बौछार

रीवा, नगर संवाददाता। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और संजय गांधी अस्पताल में जच्चा-बच्चा की मौत के मामले को लेकर मंगलवार को युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष यस घनशेरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ता स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने आवास की ओर जाने वाले मार्गों पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बनी। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की भी



जानकारी सामने आई है। पुलिस ने युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। युवा कांग्रेस नेताओं ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार, जच्चा-बच्चा की मौत के मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और

स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बनी रही। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया।

युवा कांग्रेस ने अमहिया थाने में जाकर अपनी गिरफ्तारी दी



रीवा, नगर संवाददाता। युवा कांग्रेस के सैकड़ों लोग स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के निवास के घेराव पर हुए एफआईआर में स्वयं चल कर अमहिया थाने में गिरफ्तारी दिये लेकिन पुलिस प्रशासन ने अजमानतीय धारारे 190, 191(2), 296(बी), 333, 324(2) बी.एन.एस. लगाने के बावजूद भी जेल नहीं भेजा गया। बहन कल्पना मिश्रा को न्याय दिलाने के लिये युवक कांग्रेस के साथियों ने स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव करते हुये न्याय की मांग की थी। घेराव करने वाले युवों ने प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिषेक परमार, जिला अध्यक्ष अनूप सिंह चंदेल, एनएसयुआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी, प्रदेश सचिव एनएसयुआई रवि सुमित सिंह, युवा कांग्रेस के जिला महासचिव शिवेन्द्र गुप्ता शिबू, गुड विधानसभा अध्यक्ष रोहित यादव, गोवंद ब्लॉक अध्यक्ष रामनारायण सिंह, रायपुर ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णकांत विश्वकर्मा, अनिकेश पाण्डेय के नाम से एफआईआर दर्ज की गई है।

पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य त्ववस्था चरमरा गई है: कमलेश्वर पटेल

रीवा, नगर संवाददाता। प्रदेश सहित जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली के विरोध में आदिवासी कांग्रेस एवं जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान मे किया जा रहा न्याय सत्याग्रह के तीसरे दिन सौडब्ल्यूसी सदस्य एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के मुख्यआतिथ्य एवं आदिवासी कांग्रेस विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रान्त भूरिया की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर न्याय सत्याग्रह मे उपस्थित कांग्रेसजनों को संबोधित करते हुये कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, कल्पना मिश्रा और उसके नवजात शिशु की दर्दनाक मृत्यु स्वास्थ्य विभाग की यह पहली घटना नहीं है, वरन् पूरे प्रदेश मे आयेदिन इस प्रकार की घटनायें घंटित हो रही है। श्री पटेल ने कहा कि रीवा संभागीय मुख्यालय है यहां संजय गांधी अस्पताल मे संभाग भर के लोग चिकित्सा हेतु आते हैं, जिनके



जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। न्याय सत्याग्रह की अध्यक्षता कर रहे डॉ. विक्रान्त भूरिया ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य विभाग संभालने मे पूरी तरह अक्षम साबित हुये हैं। न्याय सत्याग्रह को विधायक फुन्देलाल मारको, बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा, पूर्व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष सिंगरीली सोनम सिंह, प्रदेश महासचिव सुखेन्द्र सिंह बन्ना, प्रदेश महासचिव कविता पाण्डेय, डॉ. रश्मी सिंह पटेल, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश चंघेरिया, पूर्व विधायक राजेन्द्र मिश्रा ने संबोधित

किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष इंजी. राजेन्द्र शर्मा, मऊगंज जिला अध्यक्ष हरिलाल कोल, जिला जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय कोल, महापौर अजय मिश्रा बाबा, शहर अध्यक्ष अशोक पटेल, प्रदेश महासचिव गुरमती सिंह मंगू, पूर्व विधायक विद्यावती पटेल, प्रदेश सचिव डॉ. शीला त्यागी, जिला संगठन प्रभारी रामलखन पटेल, रामगरीब बनवासी, रमाशंकर सिंह, संगठन महासचिव रवि तिवारी, शहर संगठन महासचिव सज्जन पटेल सहित कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

शहर में निकाला मशाल जुलूस



रीवा, नगर संवाददाता। मृतिका कल्पना मिश्रा मौत मामले को लेकर कांग्रेस मुखर है। दोषी चिकित्सकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने सहित संजय गांधी अस्पताल की बदहाल व्यवस्था को लेकर युवा कांग्रेस,एनएसयुआई ने शहर में मशाल जुलूस निकाला। न्याय सत्याग्रह मशाल जुलूस में स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की गयी। उल्लेखनीय है कि कल्पना मिश्रा और गर्भस्थ नवजात की मौत के बाद एक तरफ जहाँ उनके पिता राम शिरामणि मिश्रा दोषी चिकित्सकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कमिश्नरी के सामने न्याय सत्याग्रह शुरू कर दिया। आज तीसरे दिन कांग्रेसियों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर शहर में मशाल जुलूस निकाल शासन सत्ता को चेताया।

सूची में 109 दर्ज, मौके पर शून्य

रीवा, नगर संवाददाता। लोक निर्माण विभाग में सड़कों के कई कार्य अधर में चल रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 109 कार्य ऐसे हैं जो प्रगतिरत की सूची में दर्ज हैं किन्तु इनमें से कई कार्य ऐसे हैं जहां कई महीने बीतने के बाद प्रगति शून्य बताई जा रही है। बावजूद इसके विभाग के अधिकारी ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिये तैयार नहीं हैं। बताया जा रहा है कि ये कार्य अधिकांशतः वर्ष 2023 में स्वीकृत हुये थे। कई कार्यों की समय सीमा भी समाप्त हो चुकी होगी लिहाजा ऐसे कार्यों का निरीक्षण किया जाना चाहिये किन्तु ऐसी होताने नहीं दिख रहा है। विभाग से भी निर्देश हैं कि

संबंधित जि मेदार अधिकारियों को केवल कार्यालय में बैठकर प्रगति की समीक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहिये बल्कि उन्हें मौके पर भी समय-समय पर निरीक्षण कर प्रगति की जानकारी लेनी चाहिये। आवश्यकता के अनुसार रीवा या शून्य प्रगति वाले ठेकेदारों के खिलाफ अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिये। किन्तु ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रीवा गड्डी, जोरी बाया भण्डारी तालाब रोड भुगतान 70 लाख प्रगति शून्य, छत्राढ़ खुर्द से कसियार कपास नाला दुबहा व्यय 92 लाख, प्रगति शून्य, देवास पहरखा मुख्य रोड से मड़फा शंकरजी मंदिर बाया



मझपटिया डिहिया व्यय 26 लाख प्रगति शून्य, चौराघाट हनुमना सोनोरी रोड व्यय व्यय 2.35 करोड़ प्रगति शून्य, दुआरनाथ से हरदोली बाया हायर सेकेण्डरी स्कूल व्यय 44 लाख, अटरिया शिवप्रसाद मऊगंज रोड पाडर डेम से भैयालाल पटेल टोला सब कुछ शून्य, मढी महुला से पडरिया पहुंच मार्ग जीरो,

आलमगंज से मुक्तिधाम तिवनी बाया नहर शून्य, अमहटा से पचौर रोड व्यय 31 लाख प्रगति शून्य, बड़ी डीह पहुंच मार्ग व्यय 29 लाख, बदराव तिवरियान से भेडरहा मऊ पहुंच मार्ग शून्य, बगहिया प्लान्ट से प्राथमिक स्कूल भोदहा शून्य, बरा से रहट पहुंच मार्ग व्यय 1.28 करोड़ प्रगति शून्य, भागो से

मलैगवां प्रगति शून्य, घूमन धुरकुच सोना डाबर पातिन डभौरा रोड प्रगति शून्य, चौराघाट रोड गनिगवां पुलिया से भगदेवा केवट बस्ती, छोटी सरूई से खतिलवार आदिवासी बस्ती शून्य, डेल्ली से देवगांव तिवरियान बाया सेमरी कोलगढ़ मेथौरी रोड व्यय 2.51 करोड़ प्रगति शून्य आदि इसी तरह से जिले में कई सड़कें हैं जिनका टेण्डर 2023 में हुआ था किन्तु कार्य की प्रगति आज तक शून्य है। बावजूद इसे कई कार्यों में कई लाख व एक करोड़ से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है। ऐसी सड़कों की गुणवत्ता क्या होगी जो समय सीमा में पूर्ण होने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही हैं।

हमारा प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक हम निर्णायक स्थिति पर नहीं पहुंच जाते: इंजी. शर्मा

रीवा, नगर संवाददाता। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए इंजी. राजेंद्र शर्मा ने कहा कि जिले के युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को लेकर उनसे चर्चा करने के जा रहे थे लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उन पर जबरन वॉटर कैनन का इस्तेमाल करना एवं उन्हें गिरफ्तार करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है। कांग्रेस के नौजवान आजादी की लड़ाई लड़ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विचारधारा के सिपाही हैं। लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना और सरकार से सवाल करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कायर कहकर अपनी गुलामी मानसिकता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर युवा कांग्रेस के प्रश्न सरकार और



स्वास्थ्य मंत्री से जवाब मांग रहे हैं। उनके सवालों का जवाब देने की बजाय पुलिस के बल पर आवाज दबाना और दमनात्मक कार्रवाई करना भाजपा सरकार की हताशा को दर्शाता है। सवाल यह है कि जिस प्रदेश में आमजन मानस अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पर भरोसा करता है। इस मामले में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ पर निलंबन की कार्यवाही पर अस्पताल अधीक्षक को हटाय़ा गया और मेडिकल कालेज के डीन को स्थानांतरित कर दिया गया। अभी इन घटनाओं के बाद

प्रशासन चिर निद्रा खुली है। कलेक्टर और एसपी आधी रात को औचक निरीक्षण किये हैं। श्री शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ कर्मचारियों के खिलाफ बहुत आसान हथकंडा है। सवाल यह है कि जिस प्रदेश जिम्मेदार कौन है इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। पत्रकारवार्ता को मग्न कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं पूर्व विधायक सुखेन्द्र सिंह बन्ना ने संबोधित करते हुये कहा कि यह धरना निर्णायक होगा। पत्रकार वार्ता सत्यनारायण तिवारी एवं जी.पी. त्रिपाठी उपस्थित रहे।

हम आपको बता दें कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पिछले लगभग 8.4 अरब डॉलर आंकी गई है और लक्ष्य 2033 तक इसे 44 अरब डॉलर करने पहुंचाने का है। इसलिए असली चुनौती निजी क्षेत्र बनाम इसरो नहीं, बल्कि इसरो-नेतृत्व वाले राष्ट्रीय अंतरिक्षधर्मिणी की तंत्र की सफलता है।

रणनीतिक दृष्टि से यह भारत के लिए निर्णायक मोड़ है। अब सवाल यह है कि क्या भारत उत्पादन का विस्तार करते हुए अपनी संवेदनशील तकनीक, सामरिक स्वायत्तता और वैज्ञानिक नेतृत्व को सुनिश्चित रख पाएगा। यदि संतुलन सही बैठे, तो निजी उद्योग इसरो की ताकत बढ़ाएगा; यदि पारदर्शिता और संस्थागत नियंत्रण कमजोर पड़े, तो राष्ट्रीय क्षमताओं के हस्तांतरण पर फल सवाल और गंभीर होंगे। इसरो पर फिलहाल अपना संदेश साफ कर दिया है कि वह पीछे नहीं हट रहा, बल्कि उत्पादन की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अंतरिक्ष की अगली सोमरा पर छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है।

जिलाधीश श्रीमती चौहान ने अभियान बतौर यह कार्य जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पाँच वर्ष से ऊपर का कोई भी बच्चा मेंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेशन एवं आधार पंजीयन से शेष नहीं रहना चाहिए।



सीने में दबाव या दर्द, सांस फूलना, अचानक कमजोरी, ठंडा पसीना, चक्कर या बेहोशी जैसे लक्षणों को गंजरअन्दा नहीं करना चाहिए। व्यासकर सांस में दर्द के साथ सांस लेने में परेशानी हो या दर्द हाथ, पीठ, गर्दन या जबड़े तक पहुंचे तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। ऐसे लक्षणों में घरेलू उपचार या इंतजार करने के बजाय नजदीकी अस्पताल या आपातकालीन सेवा से संपर्क करना जरूरी है।

पित्तः सीने पर हृत्थ रज्जु व्योमि के साथ चेतानीक निशान और मदद के लिए केयरटेकर को फोन करें।

A muscular man with a beard is performing a high kick or leg extension exercise outdoors. He is shirtless, wearing white pants, and is in a dynamic pose with one leg raised high and bent at the knee, holding his foot with his hands. He is standing on a wooden deck or platform, with a blurred background of trees and a building.

और उसके आसपास के हिस्से में होने वाले बदलावों को देख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आँखों की अंदरूनी तस्वीर लेने के लिए विशेष जाँच की जाती है। इससे रेटिना में रक्तस्राव, सूजन या अन्य असामान्य बदलावों का पता लगाने में मदद मिलती है। डॉक्टर मरीज को पूरी स्थिति, रक्त जाँच और आँखों की जाँच को साथ देखकर बीमारी की गंभीरता तय करते हैं। इसलिए केवल आँखों के बाहर दिखाव देने वाले बदलावों के आधार पर स्वयं बीमारी का निष्कर्ष निकालना सही नहीं है।

हाईकोर्ट में दूसरे दिन भी की गई सुनवाई,आज बचे प्रकरण रखेंगे

भोपाल में सीलिंग स्टे से जुड़े मामलों को सुन रहा है कोर्ट

भोपाल (नगर संवाददाता)

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ में दूसरे दिन मंगलवार को भोपाल में सीलिंग कार्रवाई से जुड़े विचारधीन मामलों की सुनवाई की गई। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की कोर्ट ने 102 प्रकरणों में से 55 से, ज्यादा मामलों को सुना। इससे पहले सोमवार को भी 42 प्रकरणों पर सुनवाई हो चुकी है। अब बचे प्रकरणों को सुनने के बाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।

दरअसल शहर के कई इलाकों में सीलिंग कार्रवाई के विरुद्ध लोगों ने अपनी संपत्ति पर स्टे ले रखे हैं। पिछले 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी हाईकोर्ट के स्टे हटने हैं। बताया है कि करीब 102 स्टे के केस हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ सुन रहा है। सोमवार को 42 प्रकरणों की सुनवाई के बाद मंगलवार को 55 से अधिक प्रकरण रखे गए। इन सभी के फैसले कोर्ट ने सुरक्षित रख लिए हैं। इनमें से कितनों के स्टे बरकरार रहेंगे, यह कोर्ट ही तय करेगा। इधर भोपाल नगर



शराब दुकान, पब, चाय-सुड़ा बार और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित मामले भी सुनवाई के लिए लंबित हैं। जिनमें से कुछ मामलों की सुनवाई के लिए न्यायलय ने 9 और 11 सितंबर निर्धारित की है।

15 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

इस पूरे प्रकरण को लेकर 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है। इससे पहले निगम ने अब तक शहर में 8 हजार 264 नोटिस जारी करते हुए करीब 190 संपत्तियों को सील किया है। इन सभी कार्रवाई का ब्यौरा 12 सितंबर तक नगर निगम सुप्रीम कोर्ट में देगा। इसको लेकर निगम अधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं।

निशातपुरा सवारीडिब्बा कारखाना ने 473 कोचों का किया अनुरक्षण

भोपाल। पश्चिम मध्य रेल के निशातपुरा स्थित भोपाल रेल कारखाने में कोचों का पीरियोडिक ओवरहॉलिंग कार्य निरंतर उत्कृष्टता के साथ किया जा रहा है। मुख्य कारखाना प्रबंधक के अनुसार अनुरक्षण डिपो ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम पांच माह में कुल 473 कोचों का सफलतापूर्वक अनुरक्षण कर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। केवल अगस्त में ही 101 कोचों का पीओएच किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों की सतत निगरानी में भोपाल कारखाना प्रबंधन ने यह सफलता हासिल की।

प्रवेश समय सीमा बढ़ाई

भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातक वर्ष दिवसीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष तथा स्नातकोत्तर तृतीयवर्ष की प्रवेश नवीनीकरण की समय सीमा बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है।

साक्षरता दिवस पर भोपाल डाकघर ने जारी की विशेष विरूपण मोहर



भोपाल (नगर संवाददाता)

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर मंगलवार को भोपाल जीपीओ में विशेष विरूपण मोहर जारी की गई। निर्देशक डाक सेवाएं आरएस रघुवंशी के मुख्य अतिथ्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रवर अधीक्षक डाकघर शिवांसु कुमार, डाक विभाग के अधिकारी, फिलाटेलिस्ट और नागरिक मौजूद रहे।

बता दें कि डाक टिकट

संग्रहकर्ताओं के लिए भी विशेष विरूपण मोहर का खास महत्व है। यह किसी महत्वपूर्ण अवसर की याद को दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखने का माध्यम है। आयोजन में 'साक्षरता सबके लिए' का संदेश दिया गया। महत्वपूर्ण है कि हर साल 8 सितंबर को मनाए जाने वाले साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 60वें वर्ष 2026 की थीम 'लोगों, पृथ्वी और समृद्धि के लिए साक्षरता' रही है।

बिजली कंपनियों का लाइन लॉस 24.50 प्रतिशत तक करने की तैयारी

प्रदेश में अगले साल 15 से 20% तक महंगी हो सकती है बिजली

भोपाल (नगर संवाददाता)

मध्यप्रदेश में अप्रैल 2027 से अगले पांच साल के लिए बिजली वितरण टैरिफ तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में मंगलवार को मध्यप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (MPERC) में हुई सुनवाई में बिजली उपभोक्ताओं और उद्योग प्रतिनिधियों ने बिजली कंपनियों के प्रस्तावों पर कई आपत्तियां दर्ज कराईं। सबसे बड़ा विरोध वितरण लाइन लॉस के तय मानकों को बढ़ाने को लेकर रहा। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली कंपनियां वर्तमान में जिन लाइन लॉस को मान्य करा रही हैं, उन्हें कम करने के बजाय अगले पांच साल के लिए कई क्षेत्रों में बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2027-28 में ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का लाइन लॉस 23 फीसदी और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का 24.50 फीसदी रखने की तैयारी है। वहीं वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए यह मानक 12.20 फीसदी प्रस्तावित है। मंगलवार की सुनवाई में इन बड़े हुए मानकों को मंजूरी नहीं देने की मांग की गई। सुनवाई में उद्योग प्रतिनिधियों ने भी पांच वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव पर आपत्तियां दर्ज कराईं। उनका मुख्य विरोध उद्योगों से वसूले जा रहे थ्री-पाट टैरिफ को लेकर रहा।



पांच साल के लिए तय होगा वितरण टैरिफ

MPERC की प्रस्तावित MYT Distribution Regulations, 2026 के तहत अप्रैल 2027 से मार्च 2032 तक पांच साल की नियंत्रण अवधि के लिए बिजली वितरण टैरिफ तय किया जाना है। इसी प्रक्रिया में बिजली कंपनियों के खर्च, बिजली खरीद लागत, वितरण हानि और अन्य मानकों का निर्धारण होगा। आयोग उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम टैरिफ और नियामकीय मानक तय करेगा।

शिक्षक पात्रता परीक्षा: 31 दिसंबर से पहले होगी केवल एक ही परीक्षा

भोपाल (नगर संवाददाता)

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर विभाग और शिक्षकों के संयुक्त मोर्चे के बीच गतिरोध बना हुआ है। लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने मंगलवार को संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक में स्पष्ट किया कि टीईटी देने से शिक्षकों की सीनियरिटी प्रभावित नहीं होगी। परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के लिए कराई जा रही है।

आयुक्त ने बताया कि इस साल विभाग दो बार परीक्षा नहीं करा सकेगा। एक ही परीक्षा 31 दिसंबर से पहले कराने की तैयारी है। कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने ऑफलाइन परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है, इसलिए विभाग दूसरे



विकल्पों पर विचार कर रहा है। संभावना है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के माध्यम से परीक्षा कराई जाए, हालांकि अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है।

मोर्चा परीक्षा के खिलाफ-

संयुक्त मोर्चा ने साफ किया कि वह झुझझ के पक्ष में नहीं है। मोर्चा पदाधिकारियों के अनुसार 2010 में आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षक परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। शिक्षकों से परीक्षा

लिखित निर्देश जल्द होंगे जारी

आयुक्त ने कहा कि किन शिक्षकों को परीक्षा देनी है और किन्हें नहीं, इसकी जानकारी लिखित रूप में दी जाएगी। वहीं, नई परीक्षा एजेंसी को श्वस्क्रफी परीक्षा फीस हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पर भी विचार किया जा रहा है। 2005 और 2008 में नियुक्त शिक्षकों को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के फैसले का भी विभाग इंतजार कर रहा है।

का फॉर्म नहीं भरने की अपील भी की गई है।

ई-ज्ञानसेतु यू-ट्यूब चैनल पर पढ़ सकेंगे स्नातक पाठ्यक्रमों के कोर्स

- विद्यार्थियों को आज से मिलेंगे गुणवत्तापूर्ण ई-वीडियो कंटेंट
- मंत्री परमार आज करेंगे ई-ज्ञानसेतु चैनल का शुभारंभ

भोपाल (नगर संवाददाता)

उच्च शिक्षा विभाग ने नई शिक्षा नीति के तहत क्षेत्रीय भाषाओं में शासकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों से स्नातक स्तर के विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों के लिए ई-वीडियो कंटेंट तैयार किया है। ये कंटेंट छात्रों के लिए बुधवार से शुरू किए जा रहे ई-ज्ञानसेतु चैनल में प्रसारित होंगे। इसका लाभ कॉलेज के उन हजारों छात्रों को मिलेगा, जो घर बैठे अध्ययन से स्नातक स्तर के विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों के लिए ई-कंटेंट तैयार किया जा रहा है।



और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल अध्ययन सामग्री ई-वीडियो कंटेंट के रूप में 9 सितंबर से ई-ज्ञानसेतु यू-ट्यूब चैनल पर उपलब्ध होंगे। इस नए चैनल का शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री इंंदर सिंह परमार बुधवार को करेंगे। उच्च विभाग के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के अनुरूप तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं मंत्री परमार के निर्देश पर प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों में स्थापित 10 डिजिटल स्क्रीडियो के माध्यम से स्नातक स्तर के विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों के लिए ई-कंटेंट तैयार किया जा रहा है।

62 लाख ग्रामीणों को मिला पुरखों के आवासीय जमीन का हक प्रदेश के 43 हजार गांवों का हुआ सर्वेक्षण, भूमि दस्तावेजों में दर्ज

ड्रोन ने खींची चौहद्दी | लिखी गयी सामाजिक-आर्थिक बदलाव की कहानी

भोपाल (नगर संवाददाता)

मध्यप्रदेश के 43 हजार गांवों में रहे रहे 62 लाख से अधिक लोगों को उस जगह का स्वामित्व मिल गया है, जहां पुरखों के समय से रहते आये थे। इस जमीन पर अभी तक उनके कच्चे-पक्के मकान और झोपड़ियां थीं। अभी तक वह जमीन बंदोबस्त यानी सरकारी दस्तावेजों में किसी के नाम से दर्ज नहीं थी। मकान की जमीन का स्वामित्व मिलने के बाद संबंधित लोगों के नाम वह सरकारी दस्तावेजों में दर्ज कर दी गयी है। भूमि बंदोबस्त की यह क्रांतिकारी कवायद भारत सरकार के एक विशेष ड्रोन सर्वेक्षण से संभव हो सकी है। ड्रोन ने मकानों की चौहद्दी या उसका मानचित्र निर्धारित कर सामाजिक-आर्थिक बदलाव वाली कहानी रची है।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक स्वामित्व पाने वाले अधिकतर लोग बेहद कमजोर वर्ग के थे। उन्हें अब इस जमीन का स्वामित्व मिल जाने से लोन आदि की वित्तीय मदद लेने के रास्ते भी खुल गये हैं।

जिलों की प्रगति

सबसे ज्यादा संपत्ति कार्ड

सागर	2,80,347
खंडवा	2,70,587
खरगोन	2,60,862
सिवनी	2,47,701
बालाघाट	2,34,879

सबसे कम

शहडोल	3,097
अलीराजपुर	3,608
उमरिया	4,123
सीधी	4,998
सिंगरौली	6,407



स्वामित्व योजना के तहत हुई इस कवायद का लाभ

करीब 62 लाख लोगों को मिला है। जमीन संबंधी विवादों के समाधान और संपत्तियों का मालिकाना हक तय करने 43 हजार गांवों का सर्वे कराया गया। जिसमें करीब 40 हजार से अधिक गांवों में प्रापटी कार्ड तैयार किये जा चुके हैं।

पंचायत विभाग की जानकारी के अनुसार अगस्त तक राज्य में कुल 64 लाख 19 हजार 402 संपत्ति (प्रॉपर्टी) कार्ड तैयार किए गए हैं, जबकि इनमें से 54 लाख 18 हजार 319 कार्ड हिराग्राहियों को बांटे जा चुके हैं। बताया जाता है कि केंद्र सरकार

की स्वामित्व योजना के तहत 43 हजार 104 गांवों का ड्रोन सर्वे कराया गया। इनमें 40 हजार 731 गांवों का संपत्ति कार्ड तैयार किया जा चुका है। योजना के तहत चयनित शेष 2367 गांवों का संपत्ति कार्ड तैयार करने की कवायद जारी है।

सरकार से माफ है रजिस्ट्री खर्च

मध्य सरकार ने इन संपत्तियों की आधिकारिक रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और पंचायत उपकर भी माफ कर दिया है। इससे लाभार्थियों को संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक हासिल करने की प्रक्रिया में आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ता है।

अब रहवासी जमीन पर मिल सकेगा कर्ज और दूसरी सरकारी वित्तीय मददें

योजना की स्थिति

नोटिफाइड गांव	संख्या
ड्रोन उड़ान पूरी	43,014
प्रॉपर्टी कार्ड तैयार करने वाले गांव	40,731
तैयार प्रॉपर्टी कार्ड	68,19,402
वितरित प्रॉपर्टी कार्ड	54,18,319

सागर सबसे आगे, पीछे है शहडोल

प्रॉपर्टी कार्ड तैयार करने के मामले में सागर 2,80,347 कार्ड के साथ सबसे आगे है। वहीं 3,097 कार्ड के साथ शहडोल सबसे पीछे है। राजधानी भोपाल में 45,666 कार्ड बने हैं। जबकि रीवा में 23,206 और सतना में 49,655 कार्ड तैयार हुए हैं। छतरपुर में 2,11,241, मंदसौर में 2,13,808 और शिवपुरी में 2,08,037 कार्ड तैयार किये गये हैं।

हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी

भोपाल। प्रदेश में 9वां राष्ट्रीय पोषण माह 9 सितंबर से 8 अक्टूबर तक 'हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी' थीम पर मनाया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भुरिया बुधवार को इंदौर से राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ करेंगी। अभियान में स्थानीय एवं मौसमी खाद्य पदार्थों, प्रोटीन, संतुलित आहार और बच्चों के पोषण पर विशेष जोर रहेगा। पंचायत, स्कूल और आंगनवाड़ी स्तर पर पोषण मेले, रेसिपी प्रदर्शनियां और जागरूकता कार्यक्रम होंगे। 11 सितंबर से छह वर्ष तक के बच्चों का वजन, लंबाई और ऊंचाई मापकर कागोषित बच्चों की पहचान की जाएगी। गर्भावस्था से बच्चे के पहले 1000 दिनों तक पोषण, स्तनपान और देखभाल पर परामर्श दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के शत-प्रतिशत पात्र हिराग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए विशेष चामाकन अभियान भी चलेगा। अभियान में पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

पेड़ों की कटाई पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सख्त पांच साल में सूखे या नष्ट पौधों की जगह लगाएं नए पौधे, अगली सुनवाई छह को

- भोपाल में क्षतिपूर्ति पौधारोपण की कम सर्वाइवल दर पर जताई नाराजगी

भोपाल (नगर संवाददाता)

राजधानी में विकास परियोजनाओं के लिए पेड़ों की कटाई के बदले किए जा रहे क्षतिपूर्ति पौधारोपण में लापरवाही पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की भोपाल पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। याचिकाकर्ता नितिन सक्सेना के मामले में सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि पिछले पांच साल में जो पौधे सूख या नष्ट हो गए हैं, उनकी जगह नए पौधे लगाए जाएं। उनकी नियमित सिंचाई और सुरक्षा सुनिश्चित कर 100 प्रतिशत उत्तरजीविता हासिल की जाए।



एनजीटी ने भोपाल नगर निगम और वन विभाग की रिपोर्ट में पौधों की बेहद कम जीवित रहने की दर को अस्वीकार्य बताया। अधिकरण ने पिछले पांच वर्षों में लगाए गए पौधों की औसत ऊंचाई और मोटाई का रिकॉर्ड भी मांगा है। हुजूर तहसील में लगाए जाने वाले 70 हजार और सड़क किनारे व मीडियन पर

10 हजार पौधों की साइटवार तस्वीरें भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित रिपोर्ट 30 दिन में देने को कहा गया है। अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।

जैव-चिकित्सीय

कचरे पर नाराजगी

एनजीटी ने भोपाल में जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के निपटान को लेकर भी निर्देश दिए। अपशिष्ट परिवहन वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग, रिसारोवेरी व्यवस्था और जैव-जोखिम चिन्ह अनिवार्य करने को कहा। कचरे के संग्रहण से उपचार तक की प्रक्रिया 48 घंटे में पूरी करने, नियमों का उल्लंघन करने वाले स्वास्थ्य संस्थानों पर कार्रवाई और खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए।

गुहार: 26 साल पुरानी जीपीएफ का हिसाब नहीं

- किसी का 60 हजार का बिजली बिल, किसी की मेट्रो में दुकान टूटने से पहले मुआवजे की चिंता

भोपाल (नगर संवाददाता)

सरकारी नौकरी में रहते हुए वेतन से कटी 26 साल पुरानी जीपीएफ की राशि का हिसाब अब तक नहीं मिल सका। गैस राहत विभाग के कर्मचारी प्रशांत उपाध्याय ने सेवानिवृत्ति से पहले कलेक्टर जनसुनवाई में अपनी समस्या रखी। उनका कहना है कि अगस्त 1998 में वेतन से जीपीएफ की राशि काटी गई थी, लेकिन यह रकम उनके खाते में दर्ज नहीं हुई। वर्ष 2027 में सेवानिवृत्ति प्रस्तावित है, ऐसे में कर्मचारी को अब अपने भविष्य निधि खते का बिल रिकॉर्ड दुरुस्त होने की चिंता सता रही है।मंगलवार को कलेक्ट्रेट में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन

1998 की कटौती, 2027 में सेवानिवृत्ति की चिंता

प्रशांत उपाध्याय के अनुसार उन्होंने इस मामले में पहले भी शिकायत की थी। 11 अगस्त 2026 की जनसुनवाई के बाद गैस राहत के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हुआ। उन्होंने महालेखाकार कार्यालय ग्वालिपर से मिले निर्देशों का भी आवेदन में उल्लेख किया है। कर्मचारी ने कलेक्टर से अगस्त 1998 में वेतन से काटी गई जीपीएफ राशि से संबंधित बिल, वाउचर और प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की है, ताकि उनके खाते में आवश्यक सुधार हो सके।

नियमित बिल भरती रही महिला, अचानक आया 60 हजार का बिल- मुगालिया हाट निवासी देवी बाई प्रजापति की शिकायत भी जनसुनवाई में पहुंची। उनका कहना है कि वह हर महीने नियमित रूप से बिजली बिल जमा करती हैं, लेकिन अगस्त में अचानक करीब 60 हजार रूप का बिल जारी कर दिया गया। इतनी बड़ी राशि आने से परेशान महिला ने मीटर रीडिंग और बिलिंग प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है।



कार्यालय कल भोपाल

में जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी ने लोगों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में कुल 121 आवेदन आए।

मेट्रो स्टेशन के लिए दुकान टूटेंगी, मुआवजा में नाम नहीं-

काजी कैप-बैरसिया रोड निवासी जीशान खान ने मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए टूटने वाली अपनी पुश्तैनी चाय-पान की दुकान का मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत की। उनका कहना है कि अन्य प्रभावित

लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन उनका नाम सूची में शामिल नहीं है।जीशान के मुताबिक दुकान उनके पिता की थी और उनकी मृत्यु के बाद से वे इसका संचालन कर रहे हैं।

आंगनवाड़ी का काम कराया, भुगतान अभी भी बाकी

एकतपुरी सेमरा स्थित आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक-447 में मरम्मत और पुताई का काम कराने वाले नीरज कुमार ने भी भुगतान की शिकायत की। उनका दावा है कि करीब दो लाख रूप का काम कराने के बाद 19,500 रूप के 10 चेक दिए गए, लेकिन बाद में भुगतान टेंडर प्रक्रिया से कराने की बात कही गई। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने टेंडर फीस और रिव्यूरिटी एफडीआर भी जमा की और प्रक्रिया पूरी की, लेकिन इसके बाद भी भुगतान नहीं मिला। परेराखेड़ा निवासी शाजिया खान ने आरोप लगाया कि आयुष्मान कार्ड अपडेट करने के नाम पर कुछ लोग उनके घर पहुंचे और उनके नाम से जियो पेमेंट बैंक में खाता खुलवा दिया। महिला का दावा है कि खाते में उनका मोबाइल नंबर दर्ज करने के बजाय आरोपियों ने अपना नंबर जोड़ दिया।